भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2546

दिनांक 04 दिसंबर, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए

दुग्ध उत्पादों संबंधी क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता

2546. श्री शिशिर कुमार अधिकारीः
श्री के॰ षणमुग सुंदरमः
क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने न्यूजीलैंड से दुग्ध और दुग्ध उत्पादों के आयात के संबंध में क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) जिसमें आसियान, चीन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान और दक्षिण कोरिया शामिल है, में बातचीत के दौरान कोई समझौता किया था;

(ख) यदि हां, तो क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) के अन्तर्गत ऐसे समझौते का ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या प्रस्ताव है;

(ग) क्या सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ सहित घरेलू डेयरी उत्पादकों ने मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार का प्रतिस्पर्धा में घरेलू उत्पादकता, रोजगार और दुग्ध उत्पादकों को बनाए रखने का क्या प्रस्ताव है;

(ङ) भारत में चालू वर्ष और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष हेतु दुग्ध और दुग्ध उत्पादों की कुल मात्रा कितनी है; और

(च) क्या सरकार का दुग्ध उत्पादों पर आयात शुल्क में कमी करने का कोई प्रस्ताव है?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ) : जी, नहीं। 4 नवंबर, 2019 को बैंकाक में आयोजित तीसरी आरसीईपी लीडर्स शीर्ष बैठक के दौरान, भारत ने उल्लेख किया कि क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) की वर्तमान संरचना ने पूरी तरह इसके मार्गदर्शी सिद्धांतों को पूर्णतया प्रतिबिम्बित नहीं किया या भारत के बकाया मुद्दों और चिंताओं का समाधान नहीं किया, जिसके आलोक में भारत सर्वसम्मति में शामिल नहीं हुआ। सरकार ने सहकारी दुग्ध उत्पादकों की यूनियन सहित हितधारकों के साथ परामर्श किया जिन्हें आरसीईपी के तहत इसकी स्थिति तैयार करते समय ध्यान में रखा गया।

(ङ) : पिछले चार वर्षों के दौरान भारत का वार्षिक दुग्ध उत्पादन निम्नलिखित है:

वर्ष	*दुग्ध उत्पादन(आंकड़े मिलियन टन में)
2015-16	155.5
2016-17	165.4
2017-18	176.3
**2018-19	187.7
स्रोत: *पशुपालन एवं डेयरी विभाग की 2018-19 की वार्षिक रिपोर्ट	

** पशुपालन एवं डेयरी विभाग का वार्षिक 'समेकित सैंपल सर्वे'

(च) : आज की तारीख तक ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

****